

ए०एल० बनर्जी,
आई.पी.एस.



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांक:लखनऊ:सितम्बर/3.2014

विषय- मा० उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट पिटीसन संख्या -6973/2014 श्रीमती वन्दना श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 21.5.2014 के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रश्नगत क्रिमिनल उपर्युक्त रिट के संदर्भ में मा० उच्च न्यायालय द्वारा विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्न टिप्पणी की है:-

“We deem it fit and proper to issue following directions in the matter of transfer of investigation by the higher police authorities or by the State Government:

- (a) Normally there should be no any order of transfer of investigation on an application made by an accused.
- (b) Every attempt should be made by the higher police authorities/State on receipt of an application for transfer of investigation to first ensure that the investigation is done by the concerned Police Station/concerned police authority in a fair and diligent manner.
- (c) Before passing any order on an application for transfer of investigation, the minimum expected from the State Government or from the higher police officers is to obtain a report from the Investigating Officer qua the status of the investigation and the order of the High Court, if any, in respect of the case crime number.
- d. If it is absolutely necessary to pass an order of transfer of investigation on the application of an accused, then the minimum required would be that the order must be supported by cogent reasons with reference to the material available with the authority transferring the investigation.
- (e) If necessary and permissible, an opportunity should also be afforded to the informant/ complainant before making any such order of transfer.

The directions issued by us herein above must be strictly complied with and there should be no occasion for any complaint being made to this Court that the higher authorities/State Government have disobeyed the directions, so issued.”

विवेचना स्थानान्तरण के सन्दर्भ में पार्श्वकित परिपत्रों का भी अवलोकन करने का कष्ट करें,

डीजी परिपत्र संख्या: डीजी-69/12 दिनांक 04.02.12

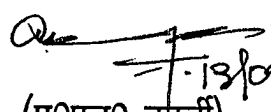
परिपत्र संख्या:एडीजी-1/12 दिनांक 12.12.12

डीजी परिपत्र संख्या: 27/2014 दिनांक 10.05.14

जिसके द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। विवेचनाओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा जो समय-समय पर जो परिपत्र निर्गत किए गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व प्रेषित दिशा -

निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


(ए०एल० बमर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
- 3.पुलिस महानिरीक्षक, ए०टी०एस०, उ०प्र० लखनऊ।
- 4.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 5.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 6.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ०प्र०।